Dainik Bhaskar 16 December, 2017

एफआरडीआई में बदलाव बेहद जरूरी : एसोचैम

एफआरडीआई बिल में जरूरी बदलाव करने की हिदायत

एजेंसी | नई दिल्ली

बैंकों में जमा आम आदमी के पैसों पर आंच न आए इसके लिए इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम ने फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस (एफआरडीआई) बिल में जरूरी बदलाव करने की हिदायत दी है।

एसोचैम ने कहा कि बिल में जमा पूंजी की सुरक्षा को लेकर तस्वीर साफ की जानी चाहिए। उसने सरकार को यह भी हिदायत दी कि वह बिल के 'बेल-इन' प्रस्ताव को हटा दे जो जमाकर्ता को भी क्रेडिट्स के तौर पर गिनता है। एफआरडीआई बिल में दिए गए बेल-इन प्रस्ताव का मतलब है कि जब भी कोई बैंक दिवालिया होगा तो उसे बचाने का भार सिर्फ सरकार ही नहीं उठाएगी, बल्कि जमाकर्ता को भी थोड़ा भार उठाना पड़ेगा।

Navodaya Times 16 December, 2017

बैंक में पैसा सुरक्षित रखने के लिए एफ.डी.आर.आई. में बदलाव जरूरी : एसोचैम

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर (एजैंसी): बैंकों में जमा आम आदमी के पैसों पर कोई आंच न आए इसके लिए इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम ने फाइनैंशियल रैजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरैंस (एफ.आर.डी.आई.) बिल में सरकार को जरूरी बदलाव करने की हिदायत दी है। एसोचैम ने कहा कि बिल में आम आदमी की जमा पूंजी की सुरक्षा को लेकर तस्वीर साफ की जानी चाहिए। उसने सरकार को यह भी हिदायत दी कि वह एफ.आर.डी.आई. बिल के 'बेल-इन' प्रस्ताव को हटा दे जो जमाकर्त्ता को भी क्रैडिट्स के तौर पर गिनता है। एफ.आर.डी.आई. बिल में दिए गए बेल-इन प्रस्ताव का मतलब है कि जब भी कोई बैंक दिवालिया होगा तो उसे बचाने का भार सिर्फ सरकार ही नहीं उठाएगी, बल्कि जमाकर्त्ता को भी थोड़ा भार उठाना पड़ेगा।

बैंकों में खत्म होगा लोगों का विश्वास

एसोचैम के महासचिव डी.एस. रावत ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो बैंकों में लोगों का जो विश्वास बना है, वह खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से सरकार के सामने नई चुनौतियां आएंगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जो पैसा बैंकों में जमा हो रहा है, इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद वह अन्य गैर-जरूरी क्षेत्रों में लगना शुरू हो जाएगा।

बैंक सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार

रावत ने कहा कि बिल में दिए गए इस प्रस्ताव को भारतीयों को ध्यान में रखकर पूरी तरह निकाल दिया जाना चाहिए। भारत में मध्यम वर्गीय व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक में रखी जमा पूंजी ही सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में पश्चिमी देशों में लागू किया गया मॉडल नहीं लाया जाना चाहिए।

Loksatya 16 December, 2017

बैंक में रखा पैसा रहे सुरक्षित, FRDI में बदलाव जरूरी : एसोचैम

नई दिल्ली, एजेंसी।

बैंकों में जमा आम आदमी के पैसों पर कोई आंच न आए, इसके लिए इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम ने फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस (एफआरडीआई) बिल में सरकार को जरूरी बदलाव करने की हिदायत दी है।

एसोचैम ने कहा है कि बिल में आम आदमी की जमा पूंजी की सुरक्षा को लेकर तस्वीर साफ की जानी चाहिए. उसने सरकार को ये भी हिदायत दी है कि वह एफआरडीआई बिल के 'बेल-इन' प्रस्ताव को हटा दे, जो जमाकर्ता को भी क्रेडिटर्स के तौर पर गिनता है।

एसोचैम ने एक बयान जारी कर बताया कि बिल के इस 'बेल-इन' प्रस्ताव ने आम लोगों के बीच बैंक में जमा अपने पैसे को लेकर संशय की भावना पैदा कर दी है। एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा कि बिल में दिए गए इस प्रस्ताव को भारतीयों को ध्यान में रखकर पूरी तरह निकाल दिया जाना चाहिए। क्योंकि आम आदमी के पैसे की रक्षा हर हाल में की जानी चाहिए। रावत ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो बैंकों में लोगों का जो विश्वास बना है वह खत्म हो जाएगा।

हिदायत

सरकार एफआरडीआई बिल के 'बेल-इन' प्रस्ताव को हटा दे

इसकी वजह से सरकार के सामने नई चुनौतियां आएंगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जो पैसा बैंकों में जमा हो रहा है इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद वह अन्य गैरजरूरी क्षेत्रों में लगना शुरू हो जाएगा। लोग बैंकों में पैसा रखने से बचने के लिए उसे रियल इस्टेट, सोना और ज्वैलरी खरीदने में खर्च करेंगे।

रावत ने आगे कहा कि भारत में मध्यम वर्गीय व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक में रखी जमा पूंजी ही सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार है। बैंक में रखी जमा पूंजी ही उनकी वित्तीय सुरक्षा होती है।

उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में पश्चिमी देशों में लागू किया गया मॉडल नहीं लाया जाना चाहिए. एफआरडीआई बेल में दिए गए बेल इन प्रस्ताव का मतलब है कि जब भी कोई बैंक दिवालिया होगा, तो उसे बचाने का भार सिर्फ सरकार ही नहीं उठाएगी, बल्कि बैंक को बचाने के लिए जमाकर्ता को भी थोड़ा भार उठाना पड़ेगा।